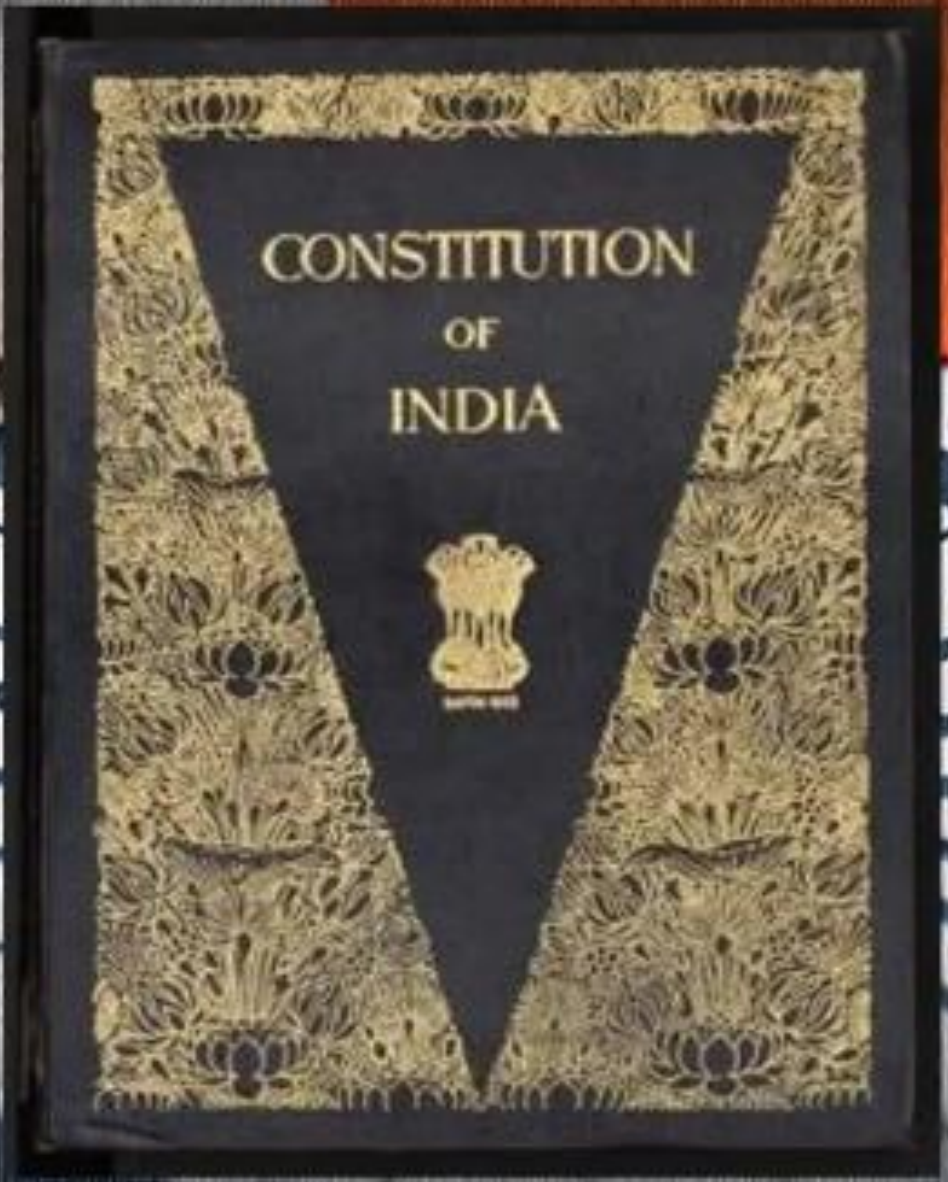




THE CONSTITUTION OF
INDIA
PREAMBLE



मूल अधिकार
Fundamental Right



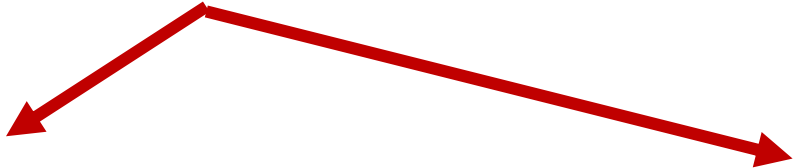
Article 31 (Right to Property/ सम्पत्ति का अधिकार)

Article 31 (1)

राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही व्यक्ति को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर सकता है।

Article 31 (2)

सम्पत्ति कब्जे में लेने का आधार



सार्वजनिक उद्देश्य हेतु
(Public Purpose)

उचित मुआवजा दिया जाए
(Compensation)



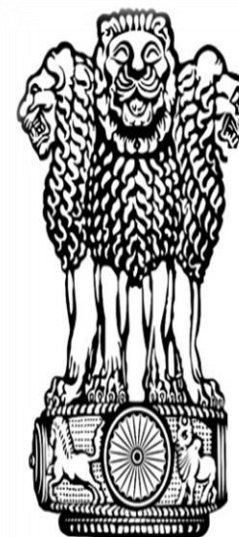
मूल अधिकार के अपवाद

1. Article 31 (A) v/s Article (14) & Article (19)
2. Article 31 (B) - 9th Schedule

↓
विषयों का न्यायिक पुर्वावलोकन (Judicial Review) नहीं

↓
I.R. Coelho Case (2007)

↓
Cut off date - 24 April, 1973



सत्यमेव जयते

FUNDAMENTAL RIGHTS

ARTICLES 12-32 PART III OF INDIAN CONSTITUTION



Important Timeline

25th CAA, 1971

- ❑ मुआवजा (Compensation) शब्द को हटा दिया गया

Amount Word Added

- ❑ Article 31 (C) Added
- ❑ Article 31 (C) - A. 39 (b) & 39 (c) v/s A. (14) & A (19), A (31)

Winner - 39 (b) & 39 (c)



- ❑ 42nd CAA, 19769 - किसी भी DPSP को पूरा करने के लिए राज्य Art. (14), (19) एवं, (31) का हनन कर सकता है।

Note

- ❑ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का अधिग्रहण करने पर Market rate पर मुआवजा देना पड़ेगा।
- ❑ यदि राज्य किसी व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि ग्रहण करता है, तो Land Ceiling के दायरे में हो

↓
Compensation of the market rate



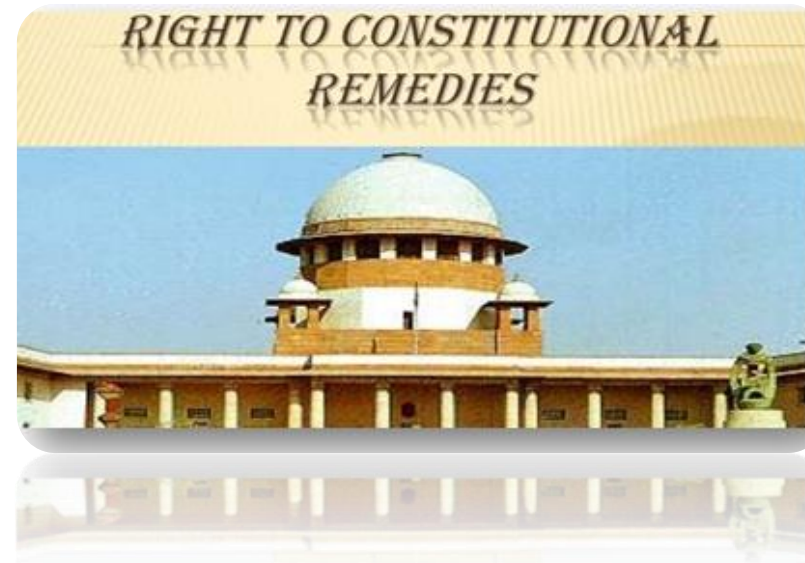
❑ 44 CAA, (1978) - सम्पत्ति का अधिकार से मूल
अधिकार का दर्जा वापस

↓
300 (A) {Part-12}



Article 32 (Right to Constitutional Remedies/ संवैधानिक उपचारों का अधिकार)

- ❑ B.R. Ambedkar के अनुसार A (32) संविधान की आत्मा है।
- ❑ A. (32) के अंतर्गत, SC मूल अधिकारों को लागू एवं हनन से रोकने हेतु रिट (Writ) जारी कर सकती है।
- ❑ HC. A. 226 के अनुसार



5 प्रकार की रिट

1. Habeas corpus बंदी प्रत्यक्षीकरण

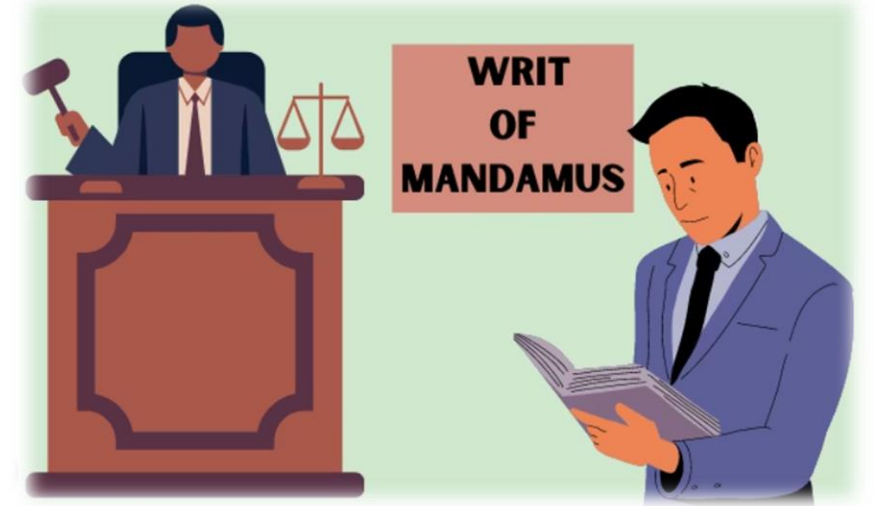
- To have the body of
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Individual Liberty) का आधार
- State + Private व्यक्ति दोनों के विरुद्ध

कहाँ लागू नहीं

- न्यायालय की अवमानना
- विधायिका (Legislature) की अवमानना
- अगर नजरबंदी कानूनी है

2. Mandamus परमादेश –

- We Command आज्ञा देना
- सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं करता।
- उच्चतम न्यायालय रिट निम्नतम न्यायालय
- राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध नहीं



3. Quo Warranto (अधिकार पृच्छा)

- ❑ न्यायालय सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच कर सकता है।



4. Certiorari (उद्देश्य)

- ❑ उच्चतम न्यायालय कोई भी केस अपने पास मंगा सकता है।
- ❑ यह रिट निर्णय देने के बाद ही लागू की जा सकती है।

5. Prohibition (प्रतिषेध)

- ❑ इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निचले न्यायालय के कार्य पर प्रतिबंध लगा सकता है।
- ❑ यह निर्णय देने के पहले प्रयोग की जाती है।

